

Jullundur would be ready by the end of this year. However, due to delay in the supply of many essential items of equipment by the manufacturers, the Station is now likely to be commissioned by March, 1979.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

541. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के विजली विभाग के कर्मचारियों ने हाल में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां की थी तथा बिजलीघरों की क्षति पहुँचाई जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ;

(ग) इन कार्रवाइयों के पीछे क्या मांगें थी ; और

(घ) उन के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) उप-केन्द्रों, स्विचिंग केन्द्रों, फीडिंग फिलर्स और सड़क प्रकाश व्यवस्था में अनेक प्रतिष्ठान बाधित पाये गये और काम नहीं कर रहे थे । जब ट्रांसफार्मर काम कर रहा था तो ट्रांसफार्मर का तेल निकालने और हाई टनशन केवल फीडिंग ट्रांसफार्मर काटने का भी प्रयास किया गया था । एच० टी० के बहुत बड़ी संख्या के नामपट तथा मीडियम वोल्टेज स्विच-बोर्ड हटा दिए गए थे उन के चलाने वाले

हैंडल निकाल दिए गए थे और अनेक फिडर पिलर पूर्णतः ध्वस्त कर दिए गए थे ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका विद्युत् प्रदाय कर्मचारी मंथ ने 24 मार्गों की परन्तु मुख्य मार्गों वर्ष 1971-72 के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी, वर्ष 1977-78 के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी, बिजली का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पृथक कक्ष का निर्माण, बिना लाग वुक के रखे हुए 150 रु० प्रतिमाह की दर से मोटर साइकल/स्कूटर भत्तों की अदायगी तथा 15 रुपये प्रति माह की दर से साइकल भत्ते की अदायगी तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा महायक अभियन्ता (विद्युत) श्रेणी-2 के पद पर कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की पदोन्नति से सम्बन्धित थी ।

(घ) उन संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ जो तोड़-फोड़ की कार्रवाई में शामिल थे पुलिस में आपराधिक मामलों दर्ज करा दिए गए थे जिस के परिणामस्वरूप 12 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । नई दिल्ली नगर पालिका के 27 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई थी ।

दिल्ली बूरवर्शन केन्द्र से लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना

542. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र पर अच्छी फिल्में और लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारण है कि आम जनता में इस बात का रोष अभी भी व्याप्त

है कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र पर सचिपूज कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं ; और

(ग) भविष्य में दूरदर्शन पर अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम दिखाए जाने के लिए सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण शर्मा) (क) से (ग) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रति जनता की प्रतिक्रियाओं की सरकार को जानकारी है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने और उन को आम पसन्द के अनुरूप तैयार करने के लिए उपलब्ध प्रमाधनों के अन्दर पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। परिवार के साथ देखने योग्य फिल्मों सहित केवल अच्छे और स्वस्थ मनोरंजन को ही प्रस्तुत करने के उद्देश्य को पूरा करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Production, Despatches and Price of Coal

543. SHRI SHAMBHU NATH TURVEDI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state the comparative figures for each year of the output, despatches and price of coal from 2 years before nationalisation of coal mines and the succeeding years thereafter?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): The Coking Coal mines were nationalised with effect from 1-5-72 and the non coking coal mines with effect from

1-5-73. The figures of output and despatches from 1970-71 onwards are as follows:—

(figures in million tonnes)

Year	Output	Despatches
1970-71	72.95	62.26
1971-72	72.42	65.52
1972-73	77.22	70.16
1973-74	78.17	68.59
1974-75	88.41	84.88
1975-76	99.68	91.96
1976-77	101.02	94.98
1977-78	101.00	99.51
1978-79(P) (April-June)	23.30	23.60 (P).

From 24-7-67 till 31-7-75 there was no statutory control on price of coal. At the time of nationalisation of non coking coal mines, the average pithead price was Rs. 37.42 per tonne. The average price, as fixed by the Central Govt., with effect from 1-4-74 was Rs. 47.42 per tonnes. The Central Government revised this price to Rs. 64.92 per tonne with effect from 1-7-75 and this is still in force.

मध्य प्रदेश में सात कपड़ा मिलों द्वारा निर्यात के लिए निर्मित कपड़ा

544: श्री हुकम चन्द कच्छवाय : वका उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा कनेगे कि :

(क) वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) के अन्तर्गत चलने वाली, सात कपड़ा मिलों द्वारा जनवरी, 1977 से जून, 1978 की विधि के दौरान विदेशों में निर्यात हेतु किन-किन किस्मों के कपड़े का निर्माण किया गया ;

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान इस कपड़े को किन-किन देशों को कितनी मात्रा में कितने मूल्य का किन पार्टियों द्वारा बेचा गया है